भारतीय कृषि के 75 वर्ष

कृषि मे मायावी विकास ?

ब्रिटिश उपनिवेश से आज़ाद हुए 75 वर्ष गुजर गए इस अवधि मे कृषि उत्पाद, संबध एवं विकास दोनों आयामो के कयी रूप परिवर्तित होते देखे। जिनका ग्रामीण जिवन पर गहरा प्रभाव हुआ। आबादी का 65 प्रतिशत हिस्सा अभी भी गांवो मे रह रहा है। इसकी बहुसंख्या कृषि पर निर्भर है। यह समय सिहांवलोकन (निरीक्षण परीक्षण) करने का है 75 वर्षो मे किसानो का कैसे भला हुआ।

इस बदलती अर्थ व्यवस्था मे, कृषि वृद्धि एवं गरीबी मे कमी सतत आर्थिक विकास की पूर्व शर्त है। कृषि हमारी खाद्य सुरक्षा ही सुनिश्चिमत नही वल्कि करोडो ग्रामीणों को आजिविका भी प्रदान करती है। विशेषज्ञो का दावा है कि कृषि किसी अन्य आर्थिक क्षेत्र की तुलना मे कृषि मे निवेश करने पर दो से तीन गुना गरिबि दूर करने पर प्रभावी हाने के साथ एक का 12 गुना लौटाती है।

पिछली सदी के प्रारंभिक दशको से ही किसानो ने सामाजिक परिवर्तनों व ब्रिटिश उप निवेश से आज़ादी के संघर्ष के लिए लाम बंध होकर महत्वपूर्ण भुमिका निभायी। स्वतंत्रता प्राप्ती के पूर्व से ही किसानो के दो मुख्य उद्देश्य रहे। सामान्ती बधुआगिरि से मुक्ती के लिए अधिकार सम्पन्नता, गांव मे सामाजिक बराबरी व आर्थिक समृद्धि के लिए जमीन जोतने वाले को मिले। आज भी हम स्वतंत्रता प्राप्ती के बाद भी इन करिश्मायी लक्ष्यों से कितने दूर है यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। स्वतंत्रता के तूरन्त बाद भूस्वमित्व की, जमीदारी, रैयतबाडी व अन्य स्वामित्वों की प्रथा का उनमोलन होना था। जमीन पर मालिकाना हक को प्रभावी रूप से परिवर्तित नहीं किया गया, जमीन का बडा हिस्सा धनी और मध्यम किसानो के हाथ मे ही रह गया। एक छोटा सा हिस्सा लघु सिंमात पिछडे एवं दलित किसानो की पहुंच मे आया देश के अधिकांश भागो मे बेमन से भुमी सुधार किये गये जो देश के विभिन्न राज्यों मे असफल रहे यह समस्या अनसुलझी रही। वर्ष 2020, 84.2 प्रतिशत किसान लघु एवं सिमांत श्रेणी मे किसान आ गए जिनके पास दो हेक्टेअर से कम जमीन है। इस बडे हिस्से के पास कुल कृषि क्षेत्र का 47.3 प्रतिशत क्षेत्रफल है शेष किसानो के पास 52.7 प्रतिशत जमीन है जो बडे और मध्यम किसानो का छोटा सा हिस्सा है। जो कुल किसानो के 13.8 प्रतिशत है। भारत मे मिट्टी वर्षा मौसम व फसलो को उंगाने मे विविधता है इस आधार पर भारत की कृषि को 13 जलवायु क्षेत्रों मे बाटा गया है सिर्फ 48.9 प्रतिशत भुमी ही सिंचित है शेष पूर्णतया वर्षा पर आधारित है सभी राज्यों मे कृषि उत्पादकता, विकासदर और किसानों की आमदनी मे भिन्नता है। जिसकी सीमा 0.25(बिहार) से 2.69(तामिलनाडू) पूरे देश की औसत 1.69 है अभी भी

ग्रामीण क्षेत्र के विकास मे भूमि का असमान मिल्कियत, उत्पादन व वितरण मे भागीदारी का बडा सवाल है जो बाधक है। बडे ज्यातदारो के पास सिंचायी के साधन कृषि मशिनरी भंडारन की सूविधा उपलब्ध है। भूमि सुधार, भूमि के गैर बराबरी के स्वामित्व को दूर करने का कारगर उपाय है जिन्हे केरल व पष्चिम बंगाल राज्यों को छोडकर बाकि देश मे प्रतीकात्मक ही लागू किया गया है।

70 के दशक मे बामदलों के भूमि संधर्षो के फलस्वरूप जो भूमी सूधार हुए उससे ग्रामीण गरिब समुदाय दलितो व पिछडी जातियों को भूमी का केवल चार प्रतिशत से भी कम हिस्सा मिल पाया छोटे किसान के पास संसाधन नहीं होने के कारण प्रकृति और बाजार की मार झेलता है। छोटि जोत कम उत्पादक होती है।

सामाजिक आर्थिक असमानता व पिछडी उत्पादन पद्वति के चलते खादान्य उत्पादन राष्ट्र को खिलाने के लिए अपर्याप्त था। आज़ादी के प्रथम दशक मे कृषि अन्य आर्थिक क्षेत्रों की तूलना मे उपे़क्षा का शिकार रहा। देश धीरे धीरे आकाल की स्थिती मे पहुंच गया। पूरा देश जहाज से आने वाले अनाज पर निर्भर था। 50 के दशक के अंतिम वर्षो मे सरकार द्वारा इस स्थिीती से उबारने के लिए निवेष बढाना शुरू किया। जिससे खाद्यानो की कमी एवं भूख मिटायी जा सके। भाखडा नंगल व नागार्जुन बांध, उर्वरक कारखाने, ग्रामीण विद्युतीकरण शुरू किया गया। इसके तहत सिचायी का बडा तंत्र खडा किया गया। खादान्य फसलो कि देशी किस्मों व देशी पशु नस्ल कम उत्पादक थी इनसे अधिक उत्पादन देने वाली किस्मो व नस्लो के विकास की आवश्यकता थी जिनसे उत्पादन बडाया जा सके इसी कडी मे ही आइसीएआर के अंतर्गत दर्जनो कृषि विश्वविद्यालय व अनुसंधान संस्थान यूएसए की सहायता से यूएस लेण्ड ग्राण्ड यूनिर्वसीटी माडल स्थापित किये गये। फोर्ड फाउण्डेशन आफ अमेरिका के राकफेलर की सलाह एवं पर्यवेक्षण मे उच्च गुणवत्ता वाले धान एवं गेहुं के बीज, फिलीपीन्स एवं मेक्सको स्थित अन्तरराष्ट्रीय फसल अनंसधान संस्थानो से आयात किये गये और उन्हे भारत के खेतो मे खेती करने के लिए परिचित किया गया। इस प्रकार 60 के दशक मे हरित क्रांती की भारत के ग्रामों मे शुरूवात हुई। किसानों द्वारा जब ये बीज सत्र दर सत्र बोये गये परिणाम तहत किसानों द्वारा संऱक्षित भुमि उर्वरकता समाप्त हाने लगी। यहां से अधिक उत्पाद देने वाले बीजो के लिए एक पूर्ण कृषि कार्यमाला की जरूरत पडी जिसमे खाद किटनाशक दवाइयां ट्रेक्टर कृषि उपकरण व डीजल आदि का उपयोग शुरू हुआ। सक्षिप्त मे फसल उत्पादन मे मे लगने वाला कृषि आदान का पूर्ण पेकेज बीज व कृषि रसायन उत्पादन करने वाले अंतरराष्ट्रीय निगमों के नियंत्रण मे आ गया। मुख्य फसलो के बीजो को स्थानीय उत्पादन पारिस्थितीकीय के अनुकुल बनाया गया सिचायी, उर्वरकों की भारी मात्रा देकर फार्म मशीनरी के प्रयोग से अधिक उत्पादन प्राप्त किया गया। नये बीजो के स्थानीय स्थिीतीयों मे प्रयोग से नये नये खरपतवार कीड़े भी आए जो भारत के किसानो के लिए बिलकुल नये थे द्वितीय विश्व युद्ध व वियतनाम पर अमरिकीय हमले के बाद रसायन उद्योगो का कृषि मे उपयोग किये जाने वाले रसायनो के उत्पादन मे लग जाने से इनका प्रयोग कृषि मे बडने लगा। इस परिप्रेक्ष्य

मे योजना बद्ध तरिके से स्थापित हरित क्रांति अमेरिकन और पश्चिमी बहु राष्ट्रीय कंपनींयों के नियंत्रण मे पडती चली गयी। उर्वरक, कीटनाशक व खरपतवारनाशी का उत्पादन व बाजार का गांवों मे विस्तार होता रहा। कृषि आदान (बीज उर्वरक, कीटनाशक व खरपतवारनाशी) कृषि मशीनरी व उपकरणों का खर्चा एवं कीमतों मे भी कई गुना बडौतरी हुई। बीज और कृषि रसायन बनाने, बेचने वाले बहुराष्ट्रीय निगमों की हरित क्रांती की सहायता से भारत के खादान्य उत्पादन व ग्रामीण अर्थ व्यवस्था पर पकड मजबुत हुई व गहरी जडे जमा ली।

नवउदारवादी सुधारो को, 21 वी सदी के प्रथम दशक मे तेजी से अमल मे लाने के कारण बहुराष्ट्रीय निगमों ने अपने उत्पादो को लेकर कृषि एवं कृषि बाजार को जकडने की चुनोती खडी कर दी। बहुराष्ट्रीय निगम पूरी कृषि ही हथियाना चाहते है। इस क्षेत्र मे चार बडे बहुराष्ट्री निगम, बायर, मोनसेन्टो, सिंजेन्टा, डाउ–डूपोन्ट व बीएएसएफ है जो बीज उर्वरक कीटनाशन, खरपतवार नाशक व फफूंद नाशीयों के कुल उत्पादन व व्यापार मे 70 प्रतिशत को नियंत्रित करती है।

सारणी 1. वर्ष 2015–16 मे (स्थिर कीमत) पर किसानो की श्रेणी बार आमदनी

क	श्रेणी	कृषक संख्या मिलियन मे	कृषक संख्या प्रतिशत मे	धारित रकबा प्रतिशत मे	प्रति कृषक वार्षिक रूपये मे	प्रति कृषक मासिक आय रूपये मे
1	सीमांत	99.86	68.53	24.15	33636	2803
2	छोटा	25.78	17.69	23.7	116196	9683
3	अर्ध मध्य्य	13.76	9.44	23.65	215656	17971
4	मध्धयम	5.48	3.76	19.96	435896	36320
5	बडा	0.83	0.57	9.04	1282125	106844
	योग औस	145.71	100	100	87614	7301

स्रोत– कृषि सांख्यिकी, 2015–16, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत वर्ष 2018

खूब खाद्य सामग्री के मध्य भूख !

खाद्यान उत्पादन 1950 मे 51 मिलियन टन से 2021 तक 310 मिलियन टन हो गया खाद्यान मे देश तथाकथित रूप से आत्म निर्भर हो गया है, निम्नलिखित सारीणी से खाद्यान्न उत्पादन को समझा जा सकता है

क	खाद्य सामग्री	उत्पादन मिलियन 1950–2021	वृद्धि दर
1	खाद्यान्न	51 से 310	6 गुनी
3	फल एवं सब्जियां	31 से 320	10 गुनी
4	दुध	17 से 210	12 गुना (विश्व मे प्रथम)
5	मछली	.75 से 14.1	18 गुना

विगत 75 वर्षो मे खाद्य सामग्री उत्पादन मे गुणात्मक वृद्धी प्राप्त हो गइ है। आत्म निर्भरता का हल्ला मचाया गया। वर्ष 2021 मे भूख सूचांक के 116 देशों के क्रम में हम 101 वं ू पर पहुंच गये। वर्ष 2020 में 94 वे पायदान पर थे। भारतीय खाद्य निगम के गोदाम क्षमता से ज्यादा खाद्यान्न भण्डार है जो गोदामों से बाहर पडा है बावजूद इसके गांवों खाद्य सामग्री की उपलब्धता घटती चली जा रही है शासन द्वारा 80 प्रतिशत लाभार्थियों को अनुदान पर किया जा रहा खाद्यान्न इस का पक्का प्रमाण है कि गांव मे भूख व कुपोषण की क्या स्थिती है। विभिन्न सर्वेक्षण के आकडे संकेत दे रहे है कि उच्च बाल मृत्यु दर आधी मॉओं और बच्चो मे कुपोषण एवं बच्चो मे बोना पन है। खाद्य उत्पादन परिवार के लिए न होकर बाजारू खपत के लिए हो गया।